



2026:AHC:68207

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस. संख्या-

2372 वर्ष 2026

दिलीप कुमार उमर आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अभिषेक कुमार सरोज, नागेंद्र बहादुर सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 69

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. श्री अभिषेक कुमार सरोज के साथ श्री नागेंद्र बहादुर सिंह, आवेदक के अधिवक्ता, श्री अनूप त्रिवेदी, अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री नितेश कुमार श्रीवास्तव, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त की गई और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत आवेदन बी.एन.एस. की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 206(बी) और एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8/21(सी)/27(ए)/29(1) के तहत अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रारंभ में, बी.एन.एस. की विभिन्न धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और जांच के दौरान एन.डी.पी.एस. अधिनियम के प्रावधानों को जोड़ा गया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बनता है और उसे जारी किए गए लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कहा जा सकता है, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम के तहत दंडनीय है। यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने मैसर्स शैली ट्रेडर्स, रांची, झारखंड से कोडीन आधारित कफ सिरप की 1,86,000 बोतलें

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



खरीदी थीं और कहा जाता है कि आवेदक ने इसे गैर-मौजूद फर्म को हस्तांतरित कर दिया था। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक को 27.11.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना, प्रथम सूचना रिपोर्ट 28.11.2025 को दर्ज की गई थी, जबकि कारण बताओ नोटिस 29.11.2025 को पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा गया था और इसे प्राप्त किया गया था जो आवेदक के पिता को 03.12.2025 को प्राप्त हुआ था और इसलिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक जांच/मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार और इच्छुक है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि आवेदक की फर्म बाहर निकलती है और संबंधित प्राधिकारी द्वारा इसका निरीक्षण किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जांच एजेंसी या अदालत द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वह पेश होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जांच में सहयोग करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है और उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और इसे इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत प्रावधान नहीं किए जा सकते हैं। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक की फर्म द्वारा भारी मात्रा में कोडीन-आधारित कफ सिरप खरीदे गए हैं और आवेदक गैर-मौजूद फर्म को उक्त कोडीन-आधारित कफ सिरप की आपूर्ति में लिप्त है और अग्रिम जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखा जाना है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुलिस ने मामले की जांच की, यह पाया गया कि आवेदक की फर्म द्वारा विभिन्न फर्मों को आपूर्ति किए गए कोडीन-आधारित कफ सिरप मौजूद नहीं पाए गए।



4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि कोडीन आधारित कफ सिरप की आपूर्ति और बिक्री एन.डी.पी.एस. अधिनियम के दायरे में नहीं आती है।
5. कहा जाता है कि आवेदक ने मेसर्स शैली ट्रेडर्स, रांची, झारखंड से कोडीन आधारित कफ सिरप की 1,86,000 बोतलें खरीदी थीं और कहा जाता है कि आवेदक ने इसे गैर-मौजूद फर्म को हस्तांतरित कर दिया था। आवेदक ने वर्तमान प्राथमिकी को रद्द करने के लिए इस न्यायालय का रुख किया, हालांकि, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने इसे अस्वीकार कर दिया।
6. जांच अभी भी चल रही है और बीरेंद्र लाल वर्मा और चार अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और तीन अन्य मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को देखते हुए, जिसने कोडीन आधारित कफ सिरप की जल्ती से संबंधित राज्य भर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने से इनकार कर दिया है और इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि यह मामला एन.डी.पी.एस. अधिनियम के दायरे में नहीं आता है।
7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए और एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों पर भी ध्यान देते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम ज़मानत देने का कोई मामला नहीं बनता है।
8. अग्रिम ज़मानत आवेदन एतद्वारा खारिज किया जाता है।

मार्च 31, 2026

आरकेएम

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)